अध्याय - 2

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारंभ जनवरी 2009 में पीएफसी के प्रबंधन के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस से हुआ। प्रारम्भ में पीएफसी के अभिलेखों की जाँच जनवरी 2009 और सितम्बर 2009 के बीच बोली लगाने के दिशानिर्देश[4] और बोली दस्तावेजों, बोली की प्रक्रिया की प्रभावकारिता और पारदर्शिता, सलाहकारों की भूमिका परिभाषित करने में स्पष्टता इत्यादि की व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में प्रबन्धन और एमओपी को क्रमशः जून 2010 और अगस्त 2010 में सूचित किया गया था।

चूंकि ईजीओएम का गठन यूएमपीपीज़ से संबंधित सभी मुख्य निर्णय लेने के लिए किया गया था और उसमें उनका कोयला संयोजन भी सम्मिलित था, एमओपी द्वारा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही थी, परिणाम के रूप में एमओपी/पीएफसी में अगस्त -सितम्बर 2011 के दौरान दोबारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिसमें अगस्त 2010 में एमओपी को अभी तक दिए गए चार यूएमपीपीज़ से संबंधित मुद्दों पर प्रबन्धन/एमओपी (ईजीओएम सहित) द्वारा की गई कार्रवाई और अन्य संबंधित मुद्दों की जाँच निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:

किसी अस्पष्टता के बिना मानक बोली दस्तावेज व्यापक थे;

बोली प्रक्रिया के लिए सलाहकारों का चयन पारदर्शी प्रणाली द्वारा किया गया था;

बोली प्रक्रिया प्रबन्धन प्रभावी रूप से और पारदर्शी तरीके से किया गया था;

यूएमपीपीज़ को प्रदत्त भूमि और कोयला संयोजन तर्कसंगत थे।

एमओपी को अक्तूबर -नवम्बर 2011 में ड्राफ्ट प्रतिवेदन जारी किया गया था और मंत्रालय की प्रतिक्रिया दिसम्बर 2011/जनवरी 2012 में प्राप्त हुई थी। एमओपी और पीएफसी के प्रबन्धन के साथ फरवरी 2012 में एक्ज़िट कान्फ्रेंस की गई थी। मंत्रालय के दृष्टिकोण के समावेशन के बाद, एमओपी को मार्च 2012 में दोबारा ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया था,

---

[4] *एमओपी ने वितरण लाइसेंसो द्वारा "विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए बोली की प्रक्रिया द्वारा टैरिफ निर्धारण के लिए दिशानिर्देश" अधिसूचित किए (जनवरी 2005)। जिन्हें इस प्रतिवेदन में "बोली दिशानिर्देश" से संदर्भित किया गया है।*

जिसके बाद मार्च 2012 में एमओपी के साथ एक और एक्ज़िट कान्फ्रेंस की गई थी। एमओपी ने सासन यूएमपीपी के विकासक रिलायन्स पावर लिमिटेड (आरपीएल) के अधिकारियों को बुलाया जिन्होंने एक्ज़िट कान्फ्रेंस के दौरान प्रस्तुतिकरण दिये। तथापि, एमओपी ने एक्ज़िट कान्फ्रेंस में बताया (मार्च 2012) कि वह आरपीएल के तथ्यों और आंकडों का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि वह वाणिज्यिक प्रकृति के थे। प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के दौरान मार्च 2012 में प्राप्त ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर एमओपी के उत्तर पर भी विचार किया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड में निम्नलिखित सम्मिलित हैः

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देश।

यूएमपीपीज़ देने के लिए विकसित और प्रयोग किए गए मानक बोली दस्तावेज।

आरएफक्यू और आरएफपी स्तर पर सलाहकारों और बोली मूल्यांकन समितियों के प्रतिवेदन।

पीएफसी और एसपीवीज़ के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद।

पीएफसी/एसपीवीज़ के निदेशक बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत्त ।

यूएमपीपीज़ को प्रदत्त विभिन्न सयोजनो से संबंधित दस्तावेज।

ईजीओएम की बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत्त

2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी अध्यायों में की गई है।

2.4 लेखापरीक्षा आभार

एमओपी और पीएफसी द्वारा लेखापरीक्षा में दिए गए सहयोग के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।